बैंक पुनर्पूंजीकरण को वापस लाने के लिए आवश्यक सुधार

साभार : लाइव मिंट **26 अक्टूबर, 2017**

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

सरकार द्वारा आक्रामक पूंजी आसव (capital infusion) का चुनाव करना एक बेहतर प्रशासन का विकल्प नहीं हो सकता।

नरेंद्र मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराने के लिए एक साहसिक कार्यक्रम में खुद को पूरी तरह से समर्पित किया है। योजना की विशिष्टता अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से सही दिशा में बढाया गया एक साहसिक कदम है। रुपये 2.11 ट्रिलियन पुनर्पूंजीकरण योजना जहाँ सरकार और वित्तीय बाजारों से 0.76 ट्रिलियन इक्विटी और रीपिपिटलाइजेशन बांडों के जरिए 1.35 खरब डॉलर का एक अन्य हिस्सा अगले दो वर्षों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अनुमान लगाया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मार्च, 2019 तक अंतरराष्ट्रीय बेसिल III आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूंजी के बारे में 1.4 - 1.7 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी।

यहाँ तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनको आगे के महीनों में निपटा लिया जाना चाहिए-

जिसमें सबसे पहला है, पुनर्पूंजीकरण विषाक्त परिसंपत्तियों के स्टॉक के साथ होता है जो अब ज्यादातर बैंकों की बैलेंस शीट में व्याप्त है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह प्रवाह के बजाय स्टॉक से संबंधित है। यह चुनौती यह सुनिश्चित करने के लिए होगी कि वैश्विक वित्तीय संकट के दोनों किनारों पर हुई प्रभावशाली औद्योगिक समूहों को उन्मत्त ऋण देने के लिए दोहराया नहीं गया है। बैंकों को अतिरिक्त पूंजी देना 2015 में घोषित इंद्रधनुष कार्यक्रम के सात महान विषयों में से एक था। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और विशेष रूप से बैंकों के निजीकरण अगले चरण में होना चाहिए।

दूसरा, इस प्रकार के हर बैंक के पुनर्पूंजीकरण को स्वाभाविक रूप से नैतिक खतरे से डर लगता है। बैंक ऋण देते वक्त पर्याप्त सावधानी नहीं बरतते हैं, जबकि वे जानते हैं कि सरकार ऋण सहायता चालू होने पर सहायता के लिए कदम उठाएगी। सरकार को चयनात्मक होना चाहिए कि किन बैंकों के प्रस्ताव पर अतिरिक्त पूंजी दी जानी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल का एक बयान के अनुसार जिन बैंकों ने अपनी ऋण समस्या से निपटने के लिए कड़ी मेहनत की है, उन्हें ताजा पूंजी तक पहुंचने में प्राथमिकता मिलेगी। इसमें बाजार अनुशासन की आवश्यकता है। कमजोर बैंकों को केवल अपने वर्तमान परिचालनों को बनाए रखने के लिए पूंजी दी जानी चाहिए, हो सकता है कि वे केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए वृद्धिशील जमा का उपयोग करें। इस बीच, बड़े उधारकर्ता जो ऋण देने में असमर्थ है, उन्हें पुनर्पूंजीकरण पर सवारी करने की अनुमति देने के बजाये दिवाला कानून के अंतर्गत लाना चाहिए।

तीसरा, सरकार को यह तय करने की जरूरत है कि मौजूदा ऋणों के मुकाबले ताजा पूंजी का अनुपात क्या होगा और नए ऋणों के लिए कितना आवंटित किया जाना चाहिए। ऋणों की कमजोर मांग को देखते हुए, यह अभी तक रोने वाली बात नहीं है, लेकिन संभव है कि अगर निवेश चक्र वास्तव में वित्तीय वर्ष 2019 में चालू हो तो कुछ तिमाहियों के बाद उधार लेना पड़ सकता है। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि रुपये 2.11 ट्रिलियन, करीब 1.3 ट्रिलियन का उपयोग प्रावधान करने के लिए किया जाएगा जबकि बाकी का उपयोग बेसिल III मानदंडों के साथ-साथ भावी ऋण वृद्धि के लिए भी किया जाएगा।

हालांकि पुनर्पूंजीकरण बांड की सही प्रकृति अभी तक स्पष्ट नहीं है, यह संभव है कि सरकार राजकोषीय घाटे में विस्तार से बचने के लिए उन्हें बजट से बाहर रखेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के लेखांकन मानदंडों के तहत, उन्हें रेखा के नीचे व्यवहार किया जाता है और राजकोषीय घाटे में बदलाव नहीं करते हैं। यह आगे ले जाने का एक तरीका सरकार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बॉन्ड जारी करने के लिए होगा, जो उनके निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाएंगे और आय में इक्विटी के रूप में वापस निवेश करेंगे। प्रभावी रूप से, ये लेन-देन नकद तटस्थ होगा और इसका असर नहीं होगा, जैसे उच्च खपत और उच्च मुद्रास्फीति, जो आमतौर पर उच्च घाटे के साथ जुड़ा हुआ है। परिचालन स्तर पर, सरकार को इस प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता है। लेकिन यह बैंकों से बांड की मांग को प्रभावित कर सकता है और पैदावार बढ़ा सकता है।

हालांकि, भले ही पुनर्पूंजीकरण के बांडों को बजट से बाहर रखा गया हो, वे अभी भी सरकार के ऋण स्टॉक में बढ़ोतरी करेंगे और ब्याज देयता बढ़ा देंगे। अनुमान के मुताबिक, ब्याज भुगतान 9 000 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है। यह भी संभव है कि इन बांडों को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और रेटिंग एजेंसियां घाटे की संख्या पर गौर करें।

हालांकि पुनर्पूंजीकरण बंधन का सहारा एक वांछित परिणाम नहीं है, यह संभवत: वैसा है जहाँ सरकार ने परिस्थितियों के अनुकूल कार्य किया हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत मुख्य रूप से एक बैंक-वित्तपोषित अर्थव्यवस्था है. इसलिए बैंकिंग प्रणाली से आवश्यक समर्थन के बिना उच्च दर से बढ़ना मुश्किल होगा। पूंजी का आविष्कार गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के संकल्प को तेज ट्रैक करेगा और छोटे और मध्यम उद्यमों को क्रेडिट के प्रवाह की बहाली के साथ आर्थिक पुनरुद्धार की सहायता करेगा।

सरकार को वित्तीय क्षेत्र में और विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार के साथ बैंक पुनर्पूंजीकरण वापस करना चाहिए। तथ्य यह है कि पुनर्पूंजीकरण बांडों का इस्तेमाल पूंजी निवेश के लिए किया जा सकता है, बेहतर शासन के लिए एक विकल्प नहीं बनना चाहिए।

इससे संबंधित तथ्य

इंद्रधनुष योजना

- देश के सरकारी बैंकों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने सात सूत्रीय इंद्रधनुष योजना बनाई है। इंद्रधनुष के 7 सूत्र इस प्रकार हैं: 1. नियुक्तियां, 2. बैंक बोर्ड ब्यूरो, 3. पूंजीकरण, 4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर दबाव हटाना, 5. सशक्तिकरण, 6. जवाबदेही की योजना बनाना, 7. प्रशासनिक सुधार।

प्रमुख उद्देश्य

- 'इंद्रधनुष' नाम की इस रणनीति का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, फंसे ऋण की मात्रा कम करना और बैंकों का प्रदर्शन सुधारना है।
- इसी के तहत सरकार ने पांच बैंकों के सीईओ-एमडी तथा चेयरमैन की नियुक्ति भी कर दी।
- सरकार सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों के लिए शेयर विकल्प लाने के बारे में सोच रही है, ताकि उनके प्रबंधन को बैंकों के प्रदर्शन में सहभागी बनाया जा सके।
- श्इंद्रधनुषश के अंतर्गत नियुक्तियों को दुरुस्त किया जाएगा, सरकारी बैंकों के प्रमुख तलाशने आदि के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की जाएगी, पुनर्पूंजीकरण के उपाय किए जाएंगे और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को कम करने में मदद की जाएगी। इससे अधिक ऋण देकर आर्थिक वृद्धि तेज करने का सरकार का उद्देश्य पूरा होगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- सरकार ने पीएसयू बैंकों को 2.11 लाख करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद किया। इसमें से 1.35 लाख करोड़ रुपये पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के रूप में आएंगे जबकि बाकी सरकारी बजट सहायता के जरिए आएगा।
- ऐसे कदम की संभावना से मंगलवार को ज्यादातर सरकारी बैंकों के शेयर चढ़े और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पिछले 10 महीने में किसी एक कारोबारी दिवस में सबसे ज्यादा चढ़ा। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.8 फीसदी चढ़ा जबकि निफ्टी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक और बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी-50 में एक फीसदी से कम की बढ़ोतरी दर्ज हुई।
- आंध्रा बैंक, सिंडिकेट बैंक और पंजाब नैशनल बैंक में पांच फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ओरियंटल बैंक, आईडीबीआई बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में तीन से पांच फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई।
- आरबीआई ने सन 1992 में बेसल एक मानक पेश किया था। बैंकों को जोखिम संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) का ध्यान रखते हुए पूंजी के साथ इसका 8 फीसदी का अनुपात रखना होता था। वर्ष 1984-85 से 1998-99 तक इन बैंकों में 20,466 करोड़ रुपये की जो राशि डाली गई उसमें से 10,987 करोड़ रुपये की राशि अकेले वर्ष 1993-94 और 1994-95 में डाली गई थी ताकि बेसल एक मानक का पालन किया जा सके। इसके बाद के वर्षों में जो भी राशि डाली गई वह कमजोर सरकारी बैंकों की मदद के लिए डाली गई।
- सरकार ने अतीत में भी सरकारी बैंकों को पूंजी मुहैया कराई है। सन 1984-85 से 1998-99 तक लगभग हर साल इन बैंकों में धन डाला गया। यह पूरी राशि करीब 20,466 करोड़ रुपये है। इसके अलावा 6,334 करोड़ रुपये की सरकारी हिस्सेदारी घाटे के बदले माफ की गई। इन बैंकों में पूंजी अपर्याप्तता की दिक्कत नई नहीं है। सन 1990 के दशक के आरंभ में भी सरकारी बैंकों में फंसे हुए कर्ज और पूंजी अपर्याप्तता की दिक्कत पैदा हुई थी। उस वक्त एक नई नियामकीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ था। ये मानक सन 1988 के बेसल समझौते के मुताबिक थे। 31 मार्च,1992 को सरकारी बैंकों की कुल संपत्ति का 6.7 फीसदी हिस्सा फंसे हुए कर्ज के रूप में था। ध्यान रहे कि उस दौर में मानक बहुत कठिन नहीं थे।
- हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं। सरकार ने रकम जुटाने की योजना बनाई है, लेकिन विश्लेषकों ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए यह खर्च व राजकोषीय घाटे के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अहम होगा, क्योंकि बजटीय आवंटन करीब 76,000 करोड़ रुपये रहेगा।
- बॉन्ड के जरिए रकम जुटाने में समस्या नहीं होगी क्योंकि सरकार समर्थित प्रतिभूतियां बाजार में पूर्व में भी आसानी से बिकी हैं और इस बार भी कोई समस्या नहीं होगी। चोकालिंगम ने कहा कि बजटीय आवंटन को देखते हुए सरकार को राजकोषीय घाटे पर थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है।

संभावित प्रश्न

प्र.: बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु आक्रामक पूंजी आसव से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में सरकार के पुनर्पूंजीकरण से संबंधित नीतिगत प्रयासों की संक्षिप्त चर्चा करें। *(200 शब्द)*

Q.: What do you think of aggressive capital infusion to improve the banking sector? In this context, briefly discuss the policy initiatives related to the Government's recapitalisation. *(200 Words)*

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322